



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. २८१]

मुद्रित दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त ७, २००८/आषाढ १६, १९३०

No. २८१]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2008/SRAVANA 16, 1930

सामाजिक ज्यादा और अधिकारिता योजना

(पिछला वर्ष घटाया)

संकलन

नई दिल्ली, ७ अगस्त, २००८

पा. सं. २००१२/१०/२००७—बी.सी.सी.—भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. २००१२/१०/२००३—बी.सी.सी., दिनांक ६ जनवरी, २००४ के तहत भीमूदा आरक्षण नीति के अंतर्गत शामिल न किए गए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों द्वारा आयोग को जारी रखने और निम्नलिखित निर्बन्धन एवं शर्तों के साथ अधिसूचना सं. २००१२/१०/२००३—बी.सी.सी., दिनांक ३ मार्च, २००५ के तहत पुनांगित और आयोग के कार्यकाल को १-८-२००८ से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का संकलन लिया है :

- (क) इस विषय पर राज्य सरकारी/संघ राज्य संग्राही और अन्य आयोगों के विचार प्राप्त करना;
- (ख) आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान के लिए मानदण्डों का सुशास्त्र देना;
- (ग) शिक्षा और सरकारी रोजगार में उपयुक्त सीमा तक कल्याणकारी उपाय और आरक्षण की महात्रा की सिफारिश करना; और
- (घ) उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए असेंब्ली अधिकारी संवैषानिक, वैधानिक तथा प्रशासनिक क्रियाविधियों का सुझाव देना।

२. आयोग भारत सरकार द्वारा आयोग को सुपुर्द एवं अनुमोदित कार्य के अनुसार कार्य को समय अनुसूची के अनुसार पूरा करेगा और १-८-२००८ से एक वर्ष की अनुबद्ध अवधि के पीछे अपने विचार-विमर्शों और सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

डॉ. विनोद अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE

AND EMPOWERMENT

(Backward Class Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 7th August, 2008

F. No. २००१२/१०/२००७-BCC.—The Government of India has resolved to continue the Commission for Economically Backward Classes not covered under the existing Reservation Policy constituted *vide* Gazette Notification No. २००१२/१०/२००३-BCC, dated 6th January, २००४ and reconstituted *vide* Notification No. २००१२/१०/२००३-BCC, dated 3rd March, २००५ and extended the term of the Commission for a period of one year w.e.f. 1-8-2008 with the following terms and conditions :

- (a) to elicit the views of State Governments/UTs and other Commissions on the subject;
- (b) to suggest criteria for identification of economically backward classes;
- (c) to recommend the welfare measures and quantum of reservation in education and Government employment to the extent as appropriate; and
- (d) to suggest the necessary constitutional, legal and administrative modalities as required for the implementation of their recommendations.

2. The Commission will complete the work entrusted to it as per time schedule submitted by Commission and approved by Government and will submit the report of its deliberations and recommendations within the stipulated period of one year w.e.f. 1-8-2008.

Dr. VINOD AGGARWAL, Jt. Secy.